महत्वपूर्ण एवं खास

कोरोना वायरस से बचने घर जा रहे श्रमिक से 12 सौ रुपये की लूट

रायपुर (आरएनएस)। विश्वव्यापी कोरोना वायरस की महामारी के चलते अनेक लोग अपने परिवारों से अलग होकर देश भर में अलग-अलग क्षेत्रों में इन दिनों फंसे हुए हैं। परिवार से छूटने के कारण प्रभावित लोग इन दिनों आंतरिक तौर पर काफी दुखी है ऐसी विपदा की घड़ी में भी धरसींवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार राजू राय आयु 40 वर्ष पिता रामनाथ राय जो प्रगति कंपनी में श्रमिक बतौर काम करता था। अपने घर अपने साथियों के साथ नीतिश कुमार, रंजीत कुमार पटेल, पप्पू कुमार शर्मा के साथ सामूहिक पदयात्रा करते हुए बिहार अपने गांव जा रहा था। जिसके पास घटनास्थल नेशनल हाइवे ग्राम मोहदी एवं तिवरैया के बीच आरोपी मोहम्मद असगर आयु 22 वर्ष कन्हैया पटेल आयु 21 वर्ष एवं उनके साथियों ने झाड़ियों के पीछे छुपकर प्रार्थियों को आते देखकर उन्हें घेरकर चाकू की नोंक पर 12 सौ रुपये की लूट की पैदल जाने वाले श्रमिक के पास 12सौ रुपये के अलावा पैसा नहीं था जिसके चलते प्रार्थी दरदर की ठोकर खाने की स्थिति में पहुंच गया।

मृतक नाबालिक के परिवार को मुख्यमंत्री ने एक लाख देने की घोषणा की

बीजापुर (आरएनएस)। लॉकडाउन में पैदल ही अपने घर का रुख करने वाली 12 वर्ष की एक लड़की जमालो मडकाम निवासी ग्राम आदेड की मौत घर पहुंचने से पहले हो गई। जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। विदित हो कि 12 वर्ष की जमालो मडकाम करीब दो महीने पहले तेलंगाना में मिर्च की खेती में काम करने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ पहली बार घर से बाहर निकली थी। करीब 100 किमी पैदल चलने के बाद उसकी मौत हो गई। उसके साथ 13 अन्य लोग भी थे, 12 वर्ष की लड़की लगातार तीन दिन तक पैदल चली और 18 अप्रैल को इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और थकान की वजह से जिले में स्थित अपने घर से 11 किमी दूर उसकी मौत हुई। मृतक जमालो अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी।

मनरेगा के तहत 145 करोड़ रूपये की 6500 कार्य स्वीकृत

रायपुर (आरएनएस)। लॉकडाउन के दौरान मुंगेली जिले मे कुछ समय के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्य बंद थे, अब फिर से प्रारंभ हो गया है। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने पर जरूरतमंद लोग रोजगार की चिंता से मुक्त हो गये है। इस योजना के तहत 145 करोड़ रूपये की 6500 कार्य स्वीकृत किये गये है। इनमे जल संरक्षण एवं सवर्धन हेतु नवीन तालाब निर्माण, तालाब एवं नरवा जीणोद्धार, कार्य के अलावा नाली निर्माण, शेड़ निर्माण आदि कार्य शामिल है। इन कार्यो मे जिले के 64 हजार 839 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। इनमे लोरमी विकास खण्ड की 26 हजार 244, विकास खण्ड मुंगेली की 20 हजार 668 और विकास खण्ड पथरिया के 17 हजार 927 श्रमिक शामिल है।

डोनेशन ऑन व्हील्स पर नगर निगम जोन 3 ने 2 लाख 1 हजार 5 सौ 16 रूपए की सहयोग राशि दी

रायपुर (आरएनएस)। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में जरुरतमंदों के सहयोग के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को रायपुर नगर निगम जोन क्रमांक-3 के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हाथ बढ़ाया। अपनी सैलरी से इन अधिकारियों व कर्मचारियों ने डोनेशन ऑन व्हील्स पर 2 लाख 1 हजार 5 सौ 16 रुपए की सहयोग राशि रायपुर ज़िला कलेक्टर डॉ. एस.भारतीदासन को भेंट की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख, नगर निगम कमिश्नर सौरभ कुमार, अपर आयुक्त पुलक भट्टाचार्य भी साथ थे। नगर निगम जोन 3 के जोन कमिश्नर अरुण साहू, कार्यपालन अभियंता प्रधान, सहायक अभियंता केके शर्मा सहित अन्य कर्मचारी ने यह सहयोग राशि एकत्रकर भेंट की है।

पिछले पांच दिनों में नहीं मिला कोई संक्रमित

» 72 घंटों में लगभग साढ़े आठ सौ कोरोना रिपोर्ट निगेटिव

कोरबा (आरएनएस)। पिछले पांच दिनों में कोरबा जिले से एम्स रायपुर और मेडिकल कालेज रायपुर भेजे गये कोई भी सेम्पल कोरोना की जांच में पाजिटिव नहीं आया है। पिछले 72 घंटों में हुई जांच में कोरबा जिले के 841सेम्पलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव मिली है इसे मिलाकर जिले में अब तक दो हजार 279 लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए जिले से दो हजार 477 सेम्पल रायपुर भेजे गये हैं, इनमें से दो हजार 307 सेम्पलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

छत्तीसगढ़ के किसानों को लॉकडाउन में 900 करोड़ रूपए का भुगतान

» राज्य के 22.48 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी

» राज्य के 15.80 लाख किसानों को 10 हजार 212 करोड़ की क्रेडिट लिमिट मंजूर

» खरीफसीजन की तैयारियां शुरू: समितियों में खाद बीज का हो रहा भण्डारण

रायपुर (आरएनएस)। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव, गरीब और किसानों के विकास के लिए लगातार ठोस कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा-निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि में कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों को फसल बीमा और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लॉकडाउन की अवधि में अब तक 900 करोड़ रूपए की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। इस अवधि में किसानों को राज्य शासन द्वारा खेती-किसानी के लिए आवश्यक छूट के साथ ही उनके उत्पाद के विक्रय की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मंत्री चौबे आज चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से चर्चा करते हुए उक्त बाते कहीं। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, खाद्य सचिव कमलप्रीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को रबी फसल बीमा की राशि का भुगतान भी शुरू कर दिया गया है। राज्य के कबीरधाम, मुंगेली और बलरामपुर जिले के 2668 किसानों को 2 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य के अन्य जिलों के किसानों को भी रबी फसल की बीमा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने फूड ग्रेन से बायो एथेनॉल बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी है। इसको देखते हुए यह उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ राज्य को बायो एथेनॉल बनाने की अनुमति शीघ्र मिल जाएगी।

मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों के हित के लिए राज्य में शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का वितरण आगामी मई माह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले सभी किसानों को किया जाएगा। चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में तरबूज, केला, पपीता के साथ ही सब्जी की भी खेती यहां के किसान करते हैं। मार्केटिंग की बेहतर व्यवस्था न होने के कारण राज्य सरकार ने इसकी खरीदी केन्द्रीय एजेंसियों के माध्यम से करने का अनुरोध किया है ताकि किसानों को उनके बेहतर लाभ मिल सके। मंत्री चौबे ने बताया कि ग्रामीणों को वृहद पैमाने पर गांव में रोजगार देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा वाटरशेड मिशन के काम भी शुरू कराए गए हैं। इससे 25 लाख मानव दिवस का सृजन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जल संसाधन विभाग के बंद पड़े निर्माणाधीन कार्यों को भी शुरू कराया गया है। विभाग के टेंडर वाले लगभग 250 करोड़ रूपए की लागत वाले निर्माण कार्य भी शुरू कराए जा रहे है ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके।

बोधघाट परियोजना का काम भी तेजी से शुरू कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खाद्य बीज का पर्याप्त मात्रा में भण्डारण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खरीफ विभिन्न फसलों के लिए 9.08 लाख क्विंटल बीज की मांग को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में अब तक 1.70 लाख क्विंटल धान बीज तथा 755 क्विंटल सोयाबीन बीज का भण्डारण प्रक्रिया केन्द्र एवं समितियों में कराया गया है।

इसी तरह राज्य में 5.8 लाख मीट्रिक टन खाद का भण्डारण किया गया है। मंत्री चौबे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से यहां के पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध की खपत नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए इससे दूध पावडर बनाने की अनुमति देने का केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।

बांध का गेट खुलने से टूटा नहर, किसानों ने जतायी चिंता

» जल्द से जल्द नहर के मरम्मत का कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा-उमाशंकर राम

रामानुजगंज (आरएनएस)। रामानुजगंज के ग्राम पंचायत भॅवरमाल में रामचंद्रपुर विकासखंड का सबसे बड़ा बांध का गेट खुलने से टूटी नहर अब यहां खतरे के रूप में मंडराने लगा है। इस खतरे को देखते हुए यहां के किसानों ने नहर की जल्द से जल्द मरम्मत के लिए जल संसाधन विभाग से मांग की है। विभाग ने नहर की मरम्मत जल्द प्रारंभ कराने का दिया आश्वासन।

गौरतलब है कि सन् 2014-15 में करीब साढे छः करोड़ रुपए लागत से ग्राम पंचायत भंवरमाल में दलको बांध एवं नहर का निर्माण जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 रामानुजगंज के द्वारा कराया गया था। बांध एवं नहर के बनने से करीब 600 हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है। रविवार को जब बांध का गेट खोला गया तो पानी के तेज बहाव से बांध से करीब 500 मीटर की दूरी पर बना नहर टूट गया, जिससे यहां खतरा मंडरा रहा है। यहां के किसानों ने टूटे नहर को जल्द से जल्द बनाने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मांग की है।

इस संबंध में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता उमाशंकर राम ने बताया कि नहर के टूटने की सूचना मिली है मौके का मुआयना करने का निर्देश उप अभियंता को दिया जा चुका है। जल्द नहर का मरम्मत करवा दिया जाएगा।

टेक्नोलॉजी के नवाचार से आसान हुई आंगनबाड़ी के बच्चों की पढ़ाई

» छत्तीसगढ़ी डिजिटल कंटेट से राह हुई आसान

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सतत रूप से राज्य में चल रहे कार्यों को देखते हुए शो मस्ट गो आन, पंक्तियां ध्यान में आती हैं। लाकडाउन में बंद पड़े आंगनबाड़ी के बच्चों के सबसे कीश्रीमती क्षणों में एक महीने का नुकसान भी उन्हें काफी पीछे ले जा सकता था, इस आशंका के चलते बच्चों को डिजिटल प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसका क्रियान्व्यन इतने तेजी से किया कि अधिकांश परिवारों तक आज यह डिजिटल कंटेट पहुंच गया है। छोटे बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध इन डिजिटल कंटेट के चलते बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी बहुत खुश हैं। डिजिटल कंटेट की भाषा छत्तीसगढ़ी होने के साथ ही इनमें छोटे बच्चों की रुचि का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें छोटी-छोटी कविताओं जैसे हाथी दादा कहां चलेस और बिल्ला अउ बड़ी नानी जैसे डिजिटल कंटेट के माध्यम से बच्चों का मनोरंजन हो रहा है और वो प्ले स्कूल की बातें भी सीख रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुर्ग के जिला कार्यक्रम अधिकारी विपिन जैन ने बताया कि डिजिटल कंटेट प्राप्त होते ही इसे सुपरवाइजर के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। इन्होंने बच्चों के अभिभावकों के व्हाटसएप ग्रूप बनाये थे जिसमें ये सारी सामग्री शेयर कर दी। साथ ही गृह भेंट के दौरान भी उन्हें इसकी जानकारी दी और बच्चों को दिखाया। गृह भेंट के माध्यम से उन बच्चों को यह ज्ञानवर्धक वीडियो दिखाये जा रहे हैं जिनके अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। प्रत्येक सोमवार को व्हाटसएप के माध्यम से दो वीडियो भेजे जाते हैं जिसे शीघ्रता से बच्चों के अभिभावकों के मोबाइल फोन तक व्हाटसएप के माध्यम से भेजा जाता है। गृह भेंट के दौरान कार्यकर्ता बच्चों को डिजिटल कंटेट तो दिखा ही रही हैं साथ ही वे अभिभावकों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा संबंधित जानकारी भी अवगत करा रही हैं।

राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक सहित महिला पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से फोन कर हालचाल जाना

» मुझे आप लोगों पर गर्व है, मैं आपके जज्बे को सलाम करती हूं: सुश्री उइके

रायपुर (आरएनएस)। कोविड संकट के इस दौर में पुलिस कर्मियों ने लाकडाउन को सफल करने में बड़ा काम किया है। महिला पुलिसकर्मियों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी अपना काम कर रही हैं। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने ऐसी ही महिला पुलिसकर्मियों को और फील्ड में अच्छा काम कर रहे पुलिस अधिकारियों को फोन लगाया। इसके लिए शुरूआत पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी से की जिनके नेतृत्व में पुलिस विभाग ने लाकडाउन के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बेहतर रखने का अच्छा काम किया है। फिर उन्होंने महिला पुलिस अधिकारियों से बात की। राज्यपाल ने कहा कि आपके सामने दोनों मोर्चों पर चुनौतियां हैं आपको घर भी देखना है और बाहर में कोविड नियंत्रण का काम भी देखना है। इसका आपने इतना संतुलित रास्ता अपनाया कि हमको आप पर गर्व होता है। आपकी कर्तव्यपरायणता के समाचार जब सुनने मिलते हैं तो मैं अभिभूत हो जाती हूँ। आप लोगों के जज्बे को सलाम करने मैंने आपको फोन लगाया है।

राज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी को बधाई देते हुए कहा कि इस समय पूरे देश में पुलिस विभाग का काम सबसे महत्वपूर्ण है। आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा कोविड-19 के बचाव में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। आप लोगों की सजगता की वजह से प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। आप लोगों द्वारा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है और आम जनता को कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अवस्थी ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने रायपुर में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अमृता सोरी और बलौदाबाजार में पदस्थ परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. अधिकारी श्रीमती अंकिता शर्मा से कहा- मैं आप लोगों के जज्बे को सलाम करती हूं। जिन परिस्थितियों में आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है वह काबिले-तारीफ है। आपने अन्य जिम्मेदारियों की अपेक्षा अपने कार्य को सबसे पहले रखा और अनेक कठिनाईयों और चुनौतियों का सामना करते हुए निरंतर उपस्थिति बनाई हुई हैं। मेरा आग्रह है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। यदि आप लोगों को कुछ आवश्यकता हो ता बताएं, प्रशासन के माध्यम से आप लोगों की अवश्य मदद की जाएगी। दोनो पुलिस अधिकारियों ने राज्यपाल के प्रति आभार प्रकट किया।

नवजात शिशु को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है सावधानीपूर्वक वजन

» मितानिन ने किया नन्हे बच्चे की धड़कन और तापमान चेक

» अभिभावकों को कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपायों की दी जानकारी

राजनांदगांव (आरएनएस)। राजनांदगांव जिले के ग्राम भंवरमरा में नवजात शिशु का जन्म 13 अप्रैल को ढेर सारी खुशियां लेकर आया। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी साहू ने नन्हें बच्चे का सावधानीपूर्वक वजन किया और मितानिन श्रीमती दुर्गा गुप्ता ने बच्चे की धड़कन और तापमान चेक किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मी देवी साहू ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला कि जिला अस्पताल में लोकेश साहू के यहां नन्हें बच्चे का प्रसव हुआ है तब उन्होंने उनके घर जाकर भेंट कर कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपायों के संबंध जानकारी दी। उन्होंने बच्चे की मां को सतत स्तनपान, माता को पौष्टिक आहार देने के लिए कहा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने बार-बार साबुन से हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करने कहा। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर टेक होम राशन भी दिया जा रहा है।

अनुपयोगी बंद पड़ी पत्थर खदानों में मछली पालन की अभिनव पहल

» मछुआ समितियों की आय में होगी वृद्धि

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने तथा मछुआ सहकारी समितियों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मछली पालन विभाग द्वारा राज्य में अनुपयोगी एवं बंद पड़ी पत्थर खदानों में मछली पालन की पहल शुरू की गई है । मछली पालन विभाग ने इसकी कार्ययोजना को अमली रूप देते हुए विधिवत इसकी शुरुआत भी राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार के गांव मनगटा से कर दी है। मनगटा गांव में पत्थर की कई खदानें हैं, जो वर्षों से अनुपयोगी एवं बंद पड़ी हैं। इस गांव की तीन खदानों को जिसका कुल रकबा लगभग 3 हेक्टेयर है, पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति बाबू नवागांव को 10 वर्षीय पट्टे पर मछली पालन के लिए दे दिया गया है। मछली विभाग द्वारा इन खदानों में मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्याखेट के लिए समिति को जाल भी उपलब्ध कराया गया है। संचालक मछली पालन ने बताया कि निकट भविष्य में डीएमएफ और विभाग के माध्यम से इन खदानों में केज कल्चर की स्थापना की जाएगी, जिससे मत्स्य पालन केज कल्चर से मत्स्य उत्पादन और समितियों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। इन खदानों के आसपास अनुपयोगी पड़ी भूमि में उद्यानिकी विभाग के सहयोग से फलदार एवं छायादार पौधों का भी रोपण किया जाएगा।

रेपिड टेस्टिंग किट से नहीं होगी जांच, राज्य शासन ने आगामी आदेश तक लगाई रोक

कोरबा (आरएनएस)। रेपिड एंटीबाडी टेस्टिंग किट से अब कोरोना की जांच नहीं की जायेगी। इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इस किट से कोरोना संक्रमण की जांच प्रतिबंधित किये जाने के बाद राज्य सरकार ने भी छत्तीसगढ़ में इसके उपयोग पर रोक लगा दी है। कोरबा जिले को दो दिन पहले ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ऐसे दो हजार किट कोरोना संक्रमण की जांच के लिए उपलब्ध कराये गये थे। पिछले दो दिनों में इन किटों से कोरबा जिले में 757 लोगों की कोरोना संक्रमण की संभावना की जांच की गई है।

लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा में डा. महंत ने राज्य सरकार के कार्यों की सराहना की

रायपुर (आरएनएस)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेसिग के माध्यम से चर्चा की। इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत भी शामिल हुए। डा. महंत ने लोकसभा अध्यक्ष से चर्चा के दौरान जहां राज्य सरकार के कार्यों की सराहना करने के साथ प्रदेश के कोटा में अध्ययनरत् छात्रों की वापसी के लिए पहल करने की अपील की।

लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ओम बिरला ने आज पूर्वान्ह 11 बजे राज्य विधान मंडलो के पीठासीन अधिकारियों से कोरोना वायरस के संक्रमण तथा उससे बचाव एवं रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय तथा लॉक डाऊन के दौरान विधायिका के क्रिया कलाप से संबंधित विभिन्न विषयों पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत अपने निवास कार्यालय स्पीकर हाऊस शंकर नगर से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से इस चर्चा में शामिल हुए।

कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करते हुए विधान सभा अध्यक्ष डा. महंत ने बताया कि 20 अप्रैल की स्थिति तक छत्तीसगढ़ में कुल 36 सेम्पल पॉजिटिव पाये गये और 25 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं और फिलहाल केवल 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज का एम्स, रायपुर में ईलाज चल रहा है।

डा. महंत ने लॉकडाउन के दौरान विधायिका के क्रियाकलाप विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि 16 मार्च से सदन में बजट पर सामान्य चर्चा प्रारंभ होनी थी लेकिन कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव के देखते हुए विधान सभा की कार्यवाही 16 मार्च को ही 26 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी गयी। दिनांक 26 मार्च को ही वर्ष 2020-21 का बजट बिना चर्चा के पारित कर उसी दिन सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU